MR. DEPUTY-SPEAKER: No qusetion of emergency. I am not allowing any d cussion here now. If there is some uis gency about it, I can understand. You knrow the procedure; you are an old Member of this House. You should go to the Busin ess Advisory Committee. I am told that it is meeting at 4 O'clock today. The Minister of Parliamentary Affairs is there and if possible he can accommodate it during the current session. I cannot say anything about it here.

SHRI S. M. BANERJEE: There was a telephonic message for him also. I only wanted to submit to him through you.....

श्री क० ना० तिवारी (बेतिया) : उपाध्यक्ष महोदय, दो बजे रोज इसी प्रकार से एक न एक सवाल यहाँ पर उठाया जाता है। मैं जानना चाहता हूं क्या हाउस का सारा बिजनेस रोक करके इनके प्रश्नों को पहले लिया जाया करेगा ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are perfectly right in raising this point. But such questions are raised not only by this side but by the other side also somtimes. People get up and I have to point out the position. Let us proceed with the Bill now.....(*Interruption.*)

SHRI SHEO NARAIN: No Government will act on telephonic message. What is he saying?

14.06 hrs.

REGISTRATION OF BIRTHS AND DEATHS BILL—*contd.*

Clause 10—contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER : We have had threadbare discussion on clause 10 and amendments were moved. I shall now put the amendments to the vote of the House. First I shall put amendment No. (old) 20 of Shri Lobo Prabhu moved in the last session.

Amendment No. (old) 20 was put and negatived.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. S. RAMASWAMY): I have tabled an official amendment similar to the one moved by Shri Beni Shanker Sharma which is No. (old) 26. So, we are accepting his amendment.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall put amendment No. (old) 26, moved in the last session, to the vote of the House. The question is:

Page 6.

omit lines 8 and 9 (26—old).

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall put amendment No. (old) 28 of Shri Kundu, moved in the last session, to the vote of the House.

Amendment No. (old) 28 was put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Amendment No. 3 is barred as identical amendment No. (old) 26 had been moved and adopted.

I shall now put Government amendment Nos. 9 and 10 to the vote of the House. The question is:

Page 6, line 10.—

for "(iii)" *substitute* "(ii)" (9)

Page 6, line 13,—

for "(iv)" *substitute* "(iii)" (10)

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put amendment No. 11 of Shri D. S. Patil to the vote of the House.

SHRI DEORAO PATIL (Yeotmal): It has been accepted by the Government.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It has not been accepted by the House. I shall put amendment No. 11 to the vote now.

(II) *Amendment No. 11 was put and negatived.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: There are three more amendments—No. 15 by Shri Om Prakash Tyagi and Nos. 16 and 17 by Dr. Ranen Sen and I shall put them to vote now.

Amendments Nos. 15, 16 and 17 were put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clause 10, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted

Clause 10, as amended, was added to the Bill

Clauses 11 and 12 were added to the Bill.

Clause 13—(*Delayed registration of births and deaths*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Shiva Chandra Jha. Are you moving your amendments?

SHRI SHIVA CHANDRA JHA (Madhubani): Yes, Sir. I move:

Page 7, lines 8 and 9, *for* "on payment of such late fee" *substitute* "without payment of any fee." (23)

Page 7, lines 19, and 20 *for* "on payment of the prescribed fee" *substitute* "without payment of any fee." (24)

उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक मोटे तौर पर अच्छा ही लगता है कि बर्थ और डैथ का रजिस्ट्रेशन हिन्दुस्तान में हो। यह एक अच्छी बात है, चूंकि हमारे समाज में यह भी पता नहीं है कि कब किसका जन्म हुआ। क्या आप बता सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का कब जन्म हुआ? कोई रेकार्ड नहीं है। जो भी आप इतिहास में देखते हैं सो काल्ड रेकार्ड है वह हकीकत में रेकार्ड नहीं है, बल्कि एक, दो साल पहले उनका जन्म हुआ था। ऐसी बहुत-सी घटनायें हैं। इसलिए यह बिल अच्छा है। मेरा जो संशोधन है वह इसलिए है कि इसमें रजिस्ट्रार होगा, चीफ रजिस्ट्रार होगा, उसके नीचे लोकल रजिस्ट्रार होंगे और एक-दूसरे को खबर करेंगे, उस पर फाइन देने का जो सवाल है वह अनुचित है। एक तो वह बेचारा खबर करेगा और इसमें फाइन देने का जो प्रोवीजन है वह मैं चाहता हूं कि निकाल दिया जाय और उसकी जगह "विदआउट पेमेंट आफ ऐनी फी" रख दिया जाय। यदि देर करके ही कोई आदमी खबर देता है, तहसीलदार, चौकीदार या गांव का मुखिया अगर देर से खबर करता है तो उस पर फाइन नहीं होना चाहिए।

इसी तरह से क्लाज़ 13 के सब-क्लाज़ (3) में "औन पेमेंट आफ दी प्रेस्काइब्ड फी" की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि जो इस बिल की दिशा है उसमें यह फिट नहीं करता इसलिए मैं चाहता हूं कि "विदआउट पेमेंट आफ ऐनी फी" रख दिया जाय।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं, और एक बात माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि यह तो अच्छी बात है कि बर्थ रेकार्ड हो। लेकिन इसमें एक सवाल आता है कि बर्थ सर्टिफिकेट में नाम तो लिखा नहीं होता। जो मजदूर सरकारी इदारों में काम करते हैं और उनके ऐक्सटेंशन का सवाल आता है तो बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं। जब हमारे देश में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम नहीं लिखा जाता है, खाली यह लिखा जाता है कि लड़का पैदा हुआ या लड़की पैदा हुई, मुन्ना पैदा हुआ या मुन्नी पैदा हुई। अब मान लीजिए कि मेरा नाम राम लाल है तो चूंकि बर्थ सर्टिफिकेट में कोई नाम नहीं लिखा होता है, क्योंकि नाम तो बाद में रखा जाता है, तो यह साबित करने के लिए कि मेरा नाम ही राम लाल है इसके लिए हनफनामा देना पड़ता है। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस दिक्कत को कैसे ओवर कम करना चाहते हैं। और लेट फी नहीं होनी चाहिए। एज के लिए स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट माँगते हैं वह नहीं मिलता तो कहते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट लाओ। बर्थ सर्टिफिकेट मिला तो

लड़का है या लड़की है, और लड़का है तो उसका नाम क्या है, यह दिक्कत होती है क्योंकि उसमें नाम तो लिखा नहीं होता ।

SHRI K. S. RAMASWAMY: The object of the Bill is to have compulsory registration of births and deaths. For delayed registration, we have prescribed certain fines in three ways: for delays of 30 days, for delays of one year and for delays of more than one year. We have prescribed certain fines for these delays, but the actual fee will be prescribed by the rules. Here, the hon. Member, Mr. Jha, has moved an amendment for the deletion of the late fee up to 30 days, and by another amendment, after one year. But for the fee between 30 days and one year he has not moved any amendment. So accepting his amendments would be meaningless. And the fee also will be very much less.

MR. DEPUTY-SPEAKER: If you accept the principle, the other things can be done later.

SHRI K. S. RAMASWAMY: We are not accepting the principle. It is only a very nominal fee.

SHRI S. M. BANERJEE: Sir, there is one difficulty. He has not given us any explanation. There is a basic difficulty. Now, you are not serving the Government even as a Deputy-Speaker. But Government servants have to produce a certificate. You need not produce a certificate. The whole thing is, they have to produce a certificate. Whether it is a boy or a girl the name is not known at the time of registration. Later on, when the name is given, the people do not accept it and they have to file an affidavit. This is a very serious matter.

SHRI K.S. RAMASWAMY: In clause 14, we have provided that where the birth of any child has been registered without a name, the parent or guardian shall give information regarding the name of the child to the Registrar within the prescribed period.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put amendments Nos. 23 and 24 to the vote of the House.

Amendments No. 23 & 24 were put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clause 13 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 13 was adopted to the Bill

Clause 14—*(Registration of name of child)*

SHRI DEORAO PATIL (Yeotmal): I beg to move:

Page 7, line 30, add at the end—

"and shall give free of charge an extract of the particulars to the person concerned"

मेरा संशोधन बहुत ही उपयुक्त है और सादा है । धारा 14 के मुताबिक रजिस्ट्रेशन आफ नेम आफ चाइल्ड का प्रोवीजन किया गया है, और रजिस्टर कराने वाला जब रजिस्ट्रार के पास जायगा, जो सूचना देगा उसका नाम बता देगा लड़के का या लड़की का, तो उसको रसीद नहीं दी जायेगी । सेक्शन 8 और 9 को देखा जाय इसमें जो सूचना देने की व्यवस्था है तो सूचना देने के बाद जो वहां अधिकारी रहता है वह उसको रसीद देता है । लेकिन इस क्लाज में यह प्रोवीजन नहीं है । जैसा कि उपाध्यक्ष महोदय आप क्लाज 12 में देखिये ।

"Extracts of registration entries to be given to informant: The Registrar shall, as soon as the registration of a birth of death has been completed give, free of charge, to the person who gives information under section 8 or section 9..."

लेकिन 14 में यह प्रोवीजन नहीं है । इसलिए मेरा अमेंडमेंट है :

"and shall give free of charge an extract of the particulars to the person concerned"

[Shri Deorao Patil]

नाम का महत्व बहुत जरूरी है और उसकी रसीद उसको मिलनी चाहिए। इसलिए मेरा संशोधन है और मैं चाहता हूं कि यह मेरा संशोधन स्वीकार किया जाय।

श्री स० मो० बनर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें यह कहा गया है कि :

> "Where a child has been registered without a name..."

लड़का या लड़की जब पैदा होता है तो फौरन तो नाम नहीं रखते पहले तो 6 दिन तक देखते हैं कि बच्चा जीता है कि नहीं तब नामकरण संस्कार होता है। और आजकल मालन्यूट्रीशन के जमाने में जिन्दा रह जाये तो बहुत भाग्य की बात है, उसके बाद नाम रखा जाता है। आप कहते हैं जहां किसी बच्चे की पैदाइश बिना नाम के रजिस्टर हुई है तो उस बच्चे के गार्जियन एक निश्चित समय में बच्चे के नाम के बारे में सूचना देंगे। लेकिन मेरा कहना यह है कि नाम तो बाद में रखा जाता है, पहले कैसे रख लेंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि पेट में बच्चा आया और नाम रखना शुरू कर दिया। बच्चा पैदा ही नहीं हुआ तो मामला ही खत्म हो गया। इसलिए यह बड़ा अनरीयलिस्टिक है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have emphasised the prevailing custom in your area. It is for the Government to consider.

SHRI S.M. BANERJEE: It is a very serious matter, Sir. Four children born to my mother survived and she named them Ram, Lakshman, Bharat and Chatrugna. My original name was Chatrugna. But in the school, nobody could pronounce my name and ultimately I had to change it to Satyendra Mohan.

गांवों में क्या होता है कि लोग अगर पूछते हैं कि तुम कब पैदा हुए तो कहने लगे कि बबूल का जब पेड़ पैदा हुआ था तो लड़का भी पैदा हुआ था। एक साथ बबूल का पेड़ लगा और तभी लड़का पैदा हुआ। हमारी बदकिस्मती है कि कोई अपरेटस नहीं है हमारे देश में। असलियत है कि जिस दिन जन्म होता है उस दिन उसका नाम नहीं रखा जाता है और बर्थ सर्टिफिकेट जो मिलता है उसमें सिर्फ यह लिखा जाता है कि मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड है। विद्याचरण शुक्ल जी घर में पूछकर देख लें कि जिस दिन वह पैदा हुए उस दिन उनका नाम नहीं रखा गया था। इसलिए मैं कहता हूं कि यह नाम देने के बारे में प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है और इसको ओवरकम करने के लिए कोई रूल बनाइये। इसमें यह दिया है :

> "the parent or guardian of such child shall give within the prescribed period give information about the name of the child". Then it is said: "from the statement of the individual or statement by the medical practitioner". In the absence of a valid document like the school Leaving Certificate or a Birth Certificate the Certificate of the doctor will be regarded as correct. I may say that I am 35 years old but the doctor my say that I am 46. One day a crazy doctor in an ordnance factory certified every appointed person as 35. Even a worker aged 20 was certified as 35. We had to refer to the Home Ministry and get it rectified. To eliminate that difficulty let them have the rules framed like that.

SHRI K.S. RAMASWAMY: As soon as a report is made about the birth of a child an extrect is given by the Registrar to the person concerned. When the child is named that person reports to the Registrar and the Registrar will then make an entry about the name in the same extract. So there will not be any duplication. with regard to framing rules the State Governments are given powers.

MR. DEPUTY-SPEAKER: If you accept the suggestion made and if you want to incorporate it in the rules you may give an assurance that you will direct the State Governments. In that case there is no difficulty. You must commit yourself on this position if you accept the contention of hon. Members.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): Why should anybody commit himself, Sir?

SHRI K.S. RAMASWAMY: We have given powers to the State Government to frame rules. The State Government will frame the rules and they will also consult us.

MR. DEPUTY-SPEAKER: They will consider the points raised here.

SHRI K. S. RAMASWAMY: Yes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is all right. I shall put the amendment, No. 12 to the vote of the House.

Amendment No. 12 was put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clause 14 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 14 was added to the Bill.

Clauses 15 to 22 were added to the Bill.

clause 23—(*Penalties*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: There are some amenmdents to clause 23.

SHRI DEORAO PATIL: Sir, I beg to move:

Page 10, line 3,—

for "fifty rupees" *substitute*—

"twenty-five rupees" (13)

DR. RANEN SEN (Barasat): Sir. I beg to move:

Page 10, line 3,—

for "fifty rupees" *substitute*—

"one hundred rupees" (19)

Page 10, line 16,—

for "ten rupees" *substitue*—

"fifty paise,. (20)

SHRI SHIVA CHANDRA JHA: Sir, I beg to move:

Page 10, lines 7 and 8,—

for "fifty rupees" *substitute*—

"one hundred rupees" (25)

Page 10, line 12,—

for "fifty rupees" *substitute*

"one hundred rupees" (26)

श्री देवराव पाटिल : उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज नम्बर 23 में जो 50 रुपये की पेनाल्टी का प्राविजन किया गया है उसके बदले मैंने अपने अमेंडमेंट के द्वारा 25 रुपये करने का सुझाव दिया है। इसमें पेनाल्टीज के क्लाज के मातहत यह लिखा हुआ है कि अगर कोई आदमी निश्चित अवधि के अन्दर रजिस्ट्रार को अपने बच्चे के जन्म या मृत्यु के सम्बन्ध में सैक्शंस 8 या 9 के अनुसार इत्तिला नहीं देता है तो उसे 50 रुपये जुर्माने की सजा दी जा सकेगी जिसे कि मैं घटाकर 25 रुपये अपने अमेंडमेंट के द्वारा करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार इस देश में 80 प्रतिशत जनता देहात में रहती है और उनकी आमदनी एक रुपये रोज से भी कम होती है और जैसा कि आपने क्लाज 23 के मातहत प्रोवाइड किया है अगर उनसे कुछ गलती हो जाती है तो उन पर 50 रुपये जुर्माना किया जायेगा तो मेरा कहना है कि इसे घटा कर 25 रुपये कर दिया जाय।

क्लाज 8(1) (ए) एन्ड (बी टु ई) जिसमें आखिर में जो ओल्डेस्ट मेल परसन होगा उस पर यह बर्थ्स और डैथ्स को रजिस्टर कराने की जिम्मेदारी डाली गई है कि लिखायेगा कि लड़का हुआ है या लड़की हुई। मेरा सुझाव यह था कि इसके लिए घर का कोई भी बड़ा आदमी जा सके। कोई भी एडल्ट जाकर रजिस्टर करा सके। लेकिन जैसा कि सैक्शन 8 मंजूर हुआ है उसके मुताबिक घर का जो

[श्री देवराव पाटिल]

सबसे ओल्डैस्ट मेल परसन होगा वही जाकर यह इनफौरमेशन दे सकेगा। मेरा सुझाव मंजूर नहीं किया गया कि प्रमुख की गैरहाजिरी में किसी भी घर के ऐडल्ट के लिए यह इनफौरमेशन सप्लाई करने का प्राविजन होना चाहिए।

इस वर्तमान क्लाज 23 में मैंने देश की आज की आर्थिक अवस्था को देखते हुए सुझाव दिया है कि 50 रुपये के बदले जुर्माने की रकम 25 रुपये कर दी जाय।

DR. RANEN SEN: The provisions of the Bill which we are now discussing show that even a good Bill, an important Bill, in the hands of certain partits or governments, turn into a very rigorous penal measure. The main object of the Bill should have been to educate people, to persuade people to go and register births and deaths. Instead of doing that, penal measures have been brought in for non-compliance with the provisions of this Bill, Thanks to 22 years of Congress rule, an overwhelming majority of the people living in the villages are still illiterate. First of all, you penalise the people by making them or keeping them illiterate. Then, taking advantage of their illiterary, you go on further penalising them for non-fulfilment of the provisions of the Bill by informing the proper authorities of birth or death within the prescribed time. This is not the way to do things. The people should be educated and persuaded to comply with the provisions of the Bill. They will do it if they know that it is for the good of the country. I hope the hon. Minister will consider the implications of the penal provisions and withdraw them.

श्री शिव चन्द्र झा : उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज नम्बर 23 पेनाल्टीज से सम्बन्धित है। उसमें बतलाया गया है कि किन किन हालतों में पैनाल्टी लगेगी।

क्लाज 23(2) में पेज 10 पर यह बतलाया गया है कि जो रजिस्ट्रार या सबरजिस्ट्रार होगा वह बर्थ और डेथ रजिस्टर करेगा, उसका तमाम हिसाब वह रक्खा करेगा। वह सरकारी कर्मचारी होगा और कोई माने नहीं हैं कि वह मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी को अंजाम न दे। अगर वह अपने काम को मुस्तैदी से नहीं करता है तो उसके माने यह होते हैं कि और विभागों में या प्रशासन में जो सरकारी कर्मचारी हैं वह भी सुस्त हो जायं इसलिए मैं इस बात को कतई नहीं पसन्द करता कि रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार की ढिलाई को किसी तरह से हलकेपन से लिया जाय। जो भी सरकारी कर्मचारी काम करते हैं जब तक वह काम करते हैं मुस्तैदी से काम करें। इसलिए यह आवश्यक है कि अगर रजिस्ट्रार या सबरजिस्ट्रार बर्थ या डैथ रजिस्टर करने में नेगलैक्ट करता है या बगैर रीजनेबुल कोज के वैसा करने से इंकार करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि वह अपने काम से, अपनी जिम्मेदारी से भागता है और गवर्नमेंट को उसकी यह नैगलैक्ट बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इस तरह की नैगलैक्ट या सुस्ती को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और इसलिए मैंने अपने अमैंडमैंट द्वारा यह चाहा है कि उस पर बजाय 50 रुपये जुर्माना होने के 100 रुपया जुर्माना किया जाय। शायद मंत्री महोदय ने कुछ और समझा। यहाँ घटाने की बात नहीं है। सरकार डाइरेक्शन देती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि रजिस्ट्रार पर जुर्माना 100 रु० हो।

श्री देवराव पाटिल : आप डेफिनिशन को देखिये।

श्री शिव चन्द्र झा : क्लाज 23 के सब-क्लाज पर मेरा संशोधन है। उसमें रजिस्ट्रार और सब-रजिस्ट्रार के ऊपर जुर्माने की बात है। मैं चाहता हूं कि वह जुर्माना 100 रु० हो।

इसी तरह से क्लाज 23 का सब-क्लाज (3) है। उसमें यह है कि जो मेडिकल डाक्टर गुजर जाने वाले आदमी को अटैंड करता है, जो वहाँ पर गया था मरीज को देखने के लिए, अगर वह सर्टिफिकेट नहीं देता है तो उसको क्या सजा दी जाएगी। यह सब-क्लाज 3 में

दिया गया है, और उसमें जुर्माने की बात है। विधेयक के अनुसार उस पर 50 रु० जुर्माना हो सकता है। मैं इसको भी उसी रूप में देखता हूं, जैसा पहले कह चुका हूं, कि डाक्टर अपनी जिम्मेदारी से भागता है। उसने उस आदमी की देख-भाल की है। वह जानता है कि वह गुजर गया, तभी उसका फर्ज हो जाता है कि वह सर्टिफिकेट दे। वह मरीज कब गुजरा, किन वजहों से गुजरा, अगर डाक्टर इसका सर्टिफिकेट नहीं देता तो वह अपने कर्तव्य से पीछे हटता है। उस पर जो 50 रु० के जुर्माने की बात रक्खी गई है वह बहुत कम है। ऐसे डाक्टर के ऊपर कम-से-कम 100 रु० जुर्माना किया जाना चाहिए।

श्री हेम राज (काँगड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो अमैंडमैंट श्री पाटिल ने रक्खा था मैं उसको सपोर्ट करता हूं। जहां तक क्लाज 23 का सम्बन्ध है, उसमें दिया गया है कि जो आदमी "(a) fails without reasonable cause to give any information....." बात उन्होंने कही है। जो देहात की जनता है वह बहुत ही गरीब है। वह इतनी पढ़ी-लिखी नहीं है कि फौरी तौर पर लोग अपना नाम दर्ज करवायेंगे। अगर उनके ऊपर जुर्माना करके इस ऐक्ट पर अमल दरामद कराना है तो मैं समझता हूं कि जो देहात की जनता है उसके साथ बड़ी बेइंसाफी होगी। श्री शिवचन्द्र झा ने कहा कि यह कम नहीं होना चाहिए। लेकिन जो क्लाज 23 है उसके सब-सेक्शन (ए), (बी) और (सी) का सम्बन्ध किसी आफिशल से नहीं है, उसका सम्बन्ध प्राइवेट सिटिजेन से है।

श्री शिवचन्द्र झा : इसके बारे में मेरा संशोधन नहीं है, वह है सब-क्लाज पर जिसमें रजिस्ट्रार के तंग करने की बात है।

श्री हेम राज : जहां तक रजिस्ट्रार का सम्बन्ध है, उसके बारे में जो कुछ है उस पर मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जहां तक प्राइवेट सिटिजेन का सम्बन्ध है, वहां पर 50 रु० जुर्माना करना ठीक नहीं है। उसको तो 25 करना ही चाहिए, बल्कि हो सके तो 5 रु० कर दिया जाना चाहए।

आज जो जरूरत है कि लोगों को एजुकेट किया जाये। जैसा डा० रणेन सेन ने कहा है आज लोगों के एजुकेशन की जरूरत है। इसलिए अगर उनके ऊपर जुर्माने की बात रखी जाय तो बहुत ज्यादती होगी। इसलिए जहां पर 50 रु० जुर्माना रक्खा गया है उसकी जगह पर 25 कर दिया जाय, बल्कि 5 रु० कर दिया जाए तो बेहतर होगा।

श्री तुलसीदास जाधव : उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज 23 में जो बात कही गई है वह मेरी समझ में नहीं आती। उसको क्लाज 8 और 9 के साथ पढ़ने से यह बात आई कि घर का जो बड़ा आदमी है, जो कर्ता है उसको खबर देनी चाहिए। अगर वह नहीं देता है तो उस पर 50 रु० तक जुर्माना हो सकता है। दूसरे जो रजिस्ट्रार है, जिसने रजिस्टर में दर्ज करने से इन्कार किया है या आनाकानी की है, उस पर भी 50 रु० तक जुर्माना हो सकता है, मेडिकल आफिसर जो है, जिसके हास्पिटल में बच्चा पैदा हुआ है या कोई मरा हो, वह भी अगर सर्टिफिकेट न दे तो उस पर भी 50 रु० जुर्माना हो सकता है। उसके बाद के जितने क्लाजेज हैं, उनके अनुसार न चलने पर भी किसी आदमी को 10 रु० तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। मेरी दृष्टि से एक जगह पर 10 रु० और दूसरी जगह पर 50 रु० होना, चाहे वह मेडिकल आफिसर हो चाहे घर का कोई आदमी हो, गलत है। इस तरह का दण्ड रखने का कोई कारण नहीं है। इस तरह से जनता को शिक्षा देने का कोई अर्थ नहीं है। अभी तक हर किसी प्रान्त में जन्म और मरण को दर्ज कराने की जो रीति है उसके लिए दण्ड देने जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। जिस दवाखाने में मृत्यु या जन्म हो, अगर कोई हस्पताल में गुजरे और वह पढ़ा-लिखा आदमी हो, तब तो मेरी समझ में आता है कि उसको 50 रु० का दण्ड दिया जाये, कोई होटल हो, रेस्टोरां हो, जहां अच्छे-

[श्री तुलसीदास जाधव]

अच्छे लोग जाते हैं, वहां अगर दण्ड रक्खा जाय तब भी कोई बात नहीं, लेकिन देहात के लोगों के लिए जो दण्ड की व्यवस्था की गई है वह गलत है। मेरी राय है कि यह दण्ड नहीं होना चाहिए। अगर दण्ड रखना ही है तो पहले आप 5 या 10 रु० रखिये, उसके बाद अगर आपका काम न चले तब आप अमैंडमैंट लाकर ज्यादा दण्ड रख सकते हैं, लेकिन शुरु-आत से ज्यादा दण्ड रखना उचित नहीं है। श्री पाटिल ने जो 25 रु० रक्खा है, मैं उससे भी सहमत नहीं हूं। हां अगर 10 रखने में कहीं पर कोई दिक्कत हो तब बाद में अमैंडमैंट लाकर उसको 25 किया जा सकता है।

SHRI ANANTRAO PATIL (Ahmednagar): I am very sorry that the persons responsible for drafting this Bill have not taken into consideration the conditions prevailing in the rural areas. There are hundreds and hundreds of villages in this country from where people cannot easily reach the taluk town or district town for registration. It is natural for them to take at least a week to go and register. The conditions may be such that the husband may stay far away from the village and suppose a child is born in that house, for that man to reach the Registrar's office will be very difficult. And suppose he fails to go in time and make the registration, a penalty of Rs. 50/-will be imposed on him. This is doing an injustice to illiterate villagers and trible people who are living in remote villages.

What has been done here? There will be a penalty of Rs. 50/- if a person fails to make the registration, but a penatly of Rs. 25/- only will be imposed in the case of a Registrar or Sub-Registrar who is an educated person, who is a responsible person and who has the duty to do this. This is a great injustice.

There is a provision that the registration should be done by the oldest man. Suppose a child is born posthumously, and there is no relative. What will be done in that case? There must be some provision for that also.

SHRI K. NARAYANA RAO (Bobbili): While I share the sentiments and enxieties expressed by my hon. friend, I feel that this is largely misconceived. If we read the clause, it will be quite clear. It does not say that each and every lapse is going to be penalised. The Bill says, '...fails without reasonable cause'. If a person fails but establishes that his failure is due to certain valid resons, he is not going to be penalised. So, many of the difficulties will be wiped out.

Secondly, only the maximum penalty has been specified. The penalty is to a maximum of Rs. 50. There is a large amount of discretion left with the penalising authority. It may be one rupee or two rupees depending on the circumstances and the other factors, and care can be taken at this juncture.

श्री ओचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने इस बात पर आपत्ति की है कि यदि कोई घर का आदमी मर जाय, या पैदा हो और यदि सबसे बड़ा वयस्क सदस्य किसी के पैदा होने या मृत्यु की सूचना किसी कारण से न दे सके, तो उसके ऊपर इतना भारी जुर्माना किया जाय। यह ठीक नहीं। आज जब अपने देश की स्थिति यह है कि लोगों में भारी अज्ञान है, मैं एक वकील के नाते कह सकता हूं कि जो भी कानून हैं, जिनको पार्लियामेंट पास करती है, वह कानून की किताबों में ही मिलेंगे लोगों को उनका पता नहीं। मैं नहीं समझता कि इस कानून के पास होने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई पग उठाये जायेंगे ग्राम ग्राम में, पहाड़ी क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में इस बात की जानकारी पहुँचाने के लिए कि अब कानून पास हो गया है और यदि किसी की पैदाइश अथवा मृत्यु की सूचना समय पर नहीं दी जायेगी तो जुर्माना किया जायेगा। जो अधिकारी इसके ऊपर अमल दरामद करायेंगे वे बिना लोगों को सभी जानकारी दिये हुए, बिना लोगों को सभी प्रावधानों से अवगत कराये हुए, करायेंगे और इसका नतीजा यह होगा कि लोगों पर भारी जुर्माने होंगे। इस एक्ट का मंशा यह है कि सरकार के पास सही जानकारी आए और

साथ ही साथ अनेक प्रसंगों पर जब लोगों को यह सिद्ध करना पड़ता है कि उनकी या उनके बच्चों की फलां-फलां जन्मतिथि है, उनको ऐसा करने में सुविधा हो। इस कानून का मंशा यह नहीं है कि रेवेन्यू इकट्ठा किया जाय या धन कमाया जाए। यह कोई टैक्स या कर नहीं है। घर के मालिक या वयस्क पर यह जिम्मेदारी डाली गयी है कि वे समय पर इसकी सूचना दें। अगर उनसे समय पर सूचना देने में भूल-चूक हो जाती है तो उन पर बड़ा भारी जुर्माना करना उचित नहीं होगा। आपने जुर्माने की जो राशि पचास रुपये रखी है, इसको आपको निश्चित रूप से कम करना चाहिये। इसको कम करके पाँच रुपये पर आपको लाना चाहिये। दल से ऊपर उठकर आपको सदन की भावनाओं का आदर करना चाहिये। सभी दलों के सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनका आपको आदर करना चाहिये और आदर करते हुए इस जमाने की आप कम करेंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं।

SHRI JAIPAL SINGH (Khunti): There is no quorum in the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The bell is being rung. Now there is quorum. Mr. Visakhapatnm.

SHRI JAIPAL SINGH: My arithmetie is not bad. There is no quorum.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It has been now ascertained that there is quorum Mr. Viswanatham.

SHRI TENNETI VISWANATHAM (Visakhapatnam): Mr. Deputy Speaker, Sir, the process of making everybody in this country a criminal must have some limits. Every year, on an average, I believe there are at least 52 lakhs of births in this country and they do not take place all in cities where the householders are educated or literate. Therefore, it is reasonable to presume that 80% of these births take place in villages and the average literacy is not more than 24-25 per cent in this country. In these circumstance I suggest that the Minister should consider the omission of the provision regarding fines. Here everybody in and around is made responsible to give the information. I can understand if this duty is imposed upon some literate people who have already been accustomed to report births and deaths.

A birth should be reported. Supposing by the time the birth is reported and by the time the person walks back 4 miles, he finds the child is dead, again he has to walk another 4 miles to give this notice. In some cases the village officers are not present. There is a group of villages in my part of the country where the same villages officer serves three or four villages. What I would suggest is that you give a period of training to this country, first restrict the fining process to responsible people and educated persons and exempt others, in the present stage of education in this country.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): I fully support the measure. Let us assume that we are discussing India as a whole where 75% is the rural population. Compared to such vast population we have 5 or 6 lakhs of post offices. If you want them to send the information in writing or post them, that will not do. It has been provided here in clause 23(1)(c) that any person who refuses to write his name, description and place of abode or to put his thumb mark in the register as required. by section 11 shall be punishable with fine which may extend to fifty rupees.

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस वक्त इस सवाल के बारे में इतना ही कहना है कि सूचना कौन देगा ? मान लीजिये कि मैं हूं और मेरी बीवी है। एक बच्चा पैदा होता है। मैं किसी को कह नहीं सकता हूं, कोई बड़ा और है नहीं जिसके द्वारा मैं सूचना भिजवा सकूं। फिर आज कल तो फैमिली प्लानिंग का जमाना है। अब मान लीजिए कि बीवी की हालत खराब हो जाती है। फौरन खबर ऐसी अवस्था में नहीं दी जा सकती है। सूचना देने में दस-बीस दिन लग सकते हैं। अगर ऐसी हालत में देरी हो जाती है तो क्या किया जा सकता है ? पहले जमाने में तो ऐसा होता था और आज भी देहातों में ऐसा होता है कि सबसे पहले

[Shri S. M. Banerjee]

हिजड़ों को खबर होती है कि फलां घर में लड़का पैदा हुआ है। वे ढोलक बजाते हुए आ जाते हैं। सब लोगों को मालूम हो जाता है कि फलां घर में लड़का पैदा हुआ है। वे तो अब सब अनएम्पलाय हो जायेंगे। बर्थ रजिस्ट्रेशन वगैरह की सब बात हम मानने के लिए तैयार हैं। कोई आदमी अगर रजिस्टर करने से इन्कार करे तब तो जरूर उस पर फाइन होना चाहिये। लेकिन सूचना देने में अगर देरी हो जाती है तो उस पर फाइन नहीं होना चाहिये और संशोधन को मान कर फाइन की जो राशि है उसको आपको कम कर देना चाहिये। लोग समझने लग गए हैं कि उनको सूचना देनी चाहिये। लोग काफी कांशस हो गए हैं। वे गलती नहीं करेंगे। लेकिन यदि किसी से किसी कारणवश देरी हो जाती है, भूल-चूक हो जाती है और उस पर पचास रुपये फाइन कर दिया जाता है तो वह यही कहेगा कि अच्छा बच्चा पैदा किया कि पचास रुपये देने पड़ गए। यह तो कलंक का टीका हो गया। लक्ष्मी घर से जाने लग गई। लड़की अगर हो जाती है तो वैसे ही लक्ष्मी जाती है और यह फाइन और उसको अदा करना पड़ेगा। इस वास्ते अगर आप संशोधन को मान लें तो बहुत अच्छा होगा।

SHRI K. S. RAMASWAMY: Sir, as regards maximum punishment, it is not necessary that maximum punishment should be imposed on poor people. The economic condition of the people will be taken into consideration by the Presiding Officer and the minimum will be imposed. Regarding Sub-clause (2), the Registrar and Sub-registrar are all officers and they will be proceeded against departmentally also; in addition to the departmental action this fine has been proposed.

In sub-clause (3) of Clause 23, regarding medical practitioners, we are fixing the fine at Rs. 50/- as in certain other cases. In Clause 24 by which the offence can be compounded, the maximum fine is fixed at Rs. 50/-. Therefore, there is no use saying that it should be more than Rs. 50/- I think this is reasonable...(*Interruptions*).

DR. RANEN SEN: What about 23(1)?

श्री मु० अ० खां (कासगंज) : यह पायंट क्लीअर नहीं हुआ है। इसमें कहा गया है कि घर का जो भी बड़ा हो, वह खबर करे। जैसा कि श्री बनर्जी ने कहा है, बच्चा होने के बाद जब बीवी मरने के करीब हो गई हो, तो क्या वह बीवी की तरफ ध्यान देगा या खबर देने के लिये भागेगा? इसमें एमेंडमेंट करनी चाहिए कि घर का कोई भी जिम्मेदार आदमी इत्तिला दे दे। हिन्दुस्तान में बच्चे का नाम उसके पैदा होने के महीने दो महीने के बाद रखा जाता है। इसलिए जब उसका नाम रखा जाय, तब इत्तिला दे दी जाये। गवर्नमेंट को ज्यादा ज़िद नहीं करनी चाहिए और इस बात को मान लेना चाहिए।

MR. DEPUTY - SPEAKER: There might be some force in all these. But it is for the Government to consider. What can I do?

श्री मु० अ० खां : हिन्दुस्तान में यह आम बात है कि बच्चा पैदा होने के बाद औरत की हालत खराब हो जाती है। ऐसी सूरत में कोई शख्स अपनी बीवी को बचायेगा या खबर देने के लिए जायेगा?

MR. DEPUTY - SPEAKER: I have called the Minister now...(*Interruptions*)

SHRI TENNETI VISWANATHAM: One clarification.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Clarification you can ask for.

SHRI TENNETI VISWANATHAM: There are quite a number of people who are going to be fined. What is the order in which they will be fined—failing (a), failing (b), failing (c)—or, will all of them be fined together?

SHRI K. S. RAMASWAMY: It is not for delayed report. There is another clause where one fails to report.

SHRI P. RAMAMURTI (Madurai): What is the difference?

SHRI K. S. RAMASWAMY: Under clause 20...

SHRI TENNETI VISWANATHAM: There are quite a number of people who are made responsible for giving the information. Will all of them be fined or some of them will be fined and in what order will they be fined—regressive or progressive order?

SHRI K. S. RAMASWAMY: One is where one fails without reasonable cause. One can explain always why he has failed.

SHRI TENNETI VISWANATHAM: Quite a number of people are made responsible.

SHRI K. S. RAMASWAMY: Sub-clause (b) says:

> gives or causes to be given, for the purpose of being inserted in any register of births and deaths, any information which he knows or believes to be false regarding any of the particulars required to be known and registered;

MR. DEPUTY-SPEAKER: When this Bill was debated on the last occasion, I said that more care should be taken while drafting this measure. I had made that observation. It is now for the Minister.

SHRI S. KANDAPPAN: How far has the Minister complied with your observation?

SHRI S.M. BANERJEE: I want some clarification. We have crossed fifty and there is no risk as far as we are concerned. But we are passing this legislation for the future generation. Let us...(*Interruptions*)

MR DEPUTY-SPEAKER: Please resume your seat. The question was raised not only by Shri Banerjee, but by several other Members. Shri Viswanatham pointed out. When the Minister has replied, he has taken everything into consideration. That is my presumption. Now, I am going to put to vote all these amendments...(*Interruptions*). I am putting amendements Nos. 13, 19, 20, 25 and 26 to Clause 23 together, unless somebody wants me to put a particular amendment separately.

AN HON. MEMBER: Amendment No. 13.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Amendment No. 13 is by Shri D.S. Patil.

AN HON. MEMBER: He says he is not pressing it.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He has moved it. I will put it to vote.

The question is:

> "Page 10, line 3,—
>
> *for* "fifty rupees" *substitute*-
>
> "twenty-five rupees" (13)

The Lok Sabha divided:

Division No. 18] **AYES** **[15.01 hrs.**

Ahmed, Shri J.	Krishna, Shri S.M.	Samanta, Shri S. C.
Banerjee, Shri S.M.	Kushwah, Shri Y.S.	Satya Narain Singh, Shri
Bharti, Shri Maharaj Singh	Mangalathumadam, Shri	Sen, Dr. Ranen
Biswas, Shri J.M.	Meghachandra, Shri M.	Shah, Shri T. P.
Deb, Shri D.N.	Misra, Shri Srinibas	Sharma, Shri Benishanker
Ghosh, Shri Ganesh	Muhammad Ismail, Shri M.	Shastri, Shri R.
Gowda, Shri M.H.	Naik, Shri G. C.	Shinkre, Shri
Goyal, Shri Shri Chand	Patil, Shri N. R.	Sonavane, Shri
Jha, Shri Shiva Chandra	Ram Charan, Shri	Viswanatham, Shri Tenneti
Kandappan, Shri S.	Ramamurti, Shri P.	Yadav, Shri Jageshwar

NOES

Agadi, Shri S. A.
Ankineedu, Shri
Barua, Shri Bedabrata
Bhandare, Shri R. D.
Bhanu Prakash Singh, Shri
Bohra, Shri Onkarlal
Chanda, Shrimati Jyotsna
Chandrika Prasad, Shri
Chaudhary, Shri Nitiraj Singh
Choudhury, Shri J. K.
Dasappa, Shri Tulsidas
Desai, Shri Morarji
Deshmukh, Shri Shivajirao S.
Dinesh Singh, Shri
Dixit, Shri G. C.
Dwivedi, Shri Nageshwar
Gandhi, Shrimati Indira
Ganesh, K. R.
Gavit Shri Tukaram
Iqbal Singh, Shri
Jadhav, Shri Tulsidas
Kavade, Shri B. R.
Khan, Shri M. A.
Khanna, Shri P. K.
Kinder Lal, Shri
Lakshmikanthamma, Shrimati
Laskar, Shri N. R.
Mahadeva Prasad, Dr.
Mahajan, Shri Vikram Chand
Mandal, Dr. P.
Marter, Shri Bhola Nath
Masuiya Din, Shri
Mishra, Shri G. S.
Naghnoor, Shri M. N.
Oraon, Shri Kartik
Pahadia, Shri Jagannath
Paokai Haokip, Shri
Parmar, Shri Bhaljibhai
Partap Singh, Shri
Parthasarathy, Shri
Pramanik, Shri J. N.
Raghu Ramaiah, Shri
Raj Deo Singh, Shri
Rajasekharan, Shri
Ram, Shri T.
Ram Sewak, Shri Chowdhary
Ram Swarup, Shri
Randhri Singh, Shri
Rao, Shri Jaganath
Rao, Shri K. Narayana
Rao, Shri J. Rampathi
Reddi, Shri G. S.
Roy, Shri Bishwanath
Roy, Shrimati Uma
Sambasivam, Shri
Sapre, Shrimati Tara
Savitri Shyam, Shrimati
Sayeed, Shri P. M.
Sayyad Ali, Shri
Sen, Shri Dwipayan
Sen, Shri P. G.
Sethuraman, Shri N.
Shambhu Nath, Shri
Shankaranand, Shri
Sharma, Shri Naval Kishore
Sheo Narain, Shri
Shukla, Shri S. N.
Shukla, Shri Vidya Charan
Tiwary, Shri D. N.
Virbhadra Singh, Shri
Vyas, Shri Ramesh Chandra
Yadav, Shri Chandra Jeet

MR. DEPUTY-SPEAKER: The result* of the division is *Ayes; 30 Noes: 72.*

The motion was negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put the other amendments to clause 23 to vote.

Amendments Nos. 19, 20, 25, 26 were put and negatived

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clause 23 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 23 was added to the Bill.

Clause 24—(Power to compound, offences)

SHRI DEORAO PATIL: I beg to move:

Page 10, line 26, *for* 'fifty rupees' *substitute* 'one hundred rupees'. (14)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह संशोधन ग्राफेंस को कम्पाउंड करने के बारे में है। हम देखते हैं कि सरकार की दृष्टि में एक सरकारी कर्मचारी की प्रतिष्ठा देश के साधारण नागरिक से ज्यादा है।

लोक प्रतिनिधि से कर्मचारियों की प्रतिष्ठा ज्यादा है और जनता से भी कर्मचारी की प्रतिष्ठा ज्यादा है। धारा 23 देखिये। जो कोई भी रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार जन्म या मृत्यु को रजिस्टर नहीं करता है या नेग्लेक्ट करता है उसको 25 रुपये जुर्माना और सामान्य गरीब मजदूर जो है वह अगर वही गुनाह करता है तो उसको 50 रुपये जुर्माना होगा और बाद में जुर्माना करने के बाद, कोर्ट में केस

*The following Members also recorded their votes for AYES: Sarvashri H. Ajmal Khan and D. Amat.

दाखिल होने के बाद कोई अधिकारी कम्पाउंड केस करता है तो 50 रुपया देने पर वह केस खत्म हो जायगा। मैंने पहले ही बताया कि इस देश में गरीबी का सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देखा जाय यो इस देश में 80 प्रतिशत जनता जो है उसमें से 50 प्रतिशत जनता की रोजी 1 रुपये रोज पर चलती है। वह कम्पाउंड केस करने के लिए नहीं जायगा। उसको पनिशमेंट हो जाय वह दे देगा। लेकिन जो अमीर लोग हैं या कर्मचारी लोग हैं वह जब क्राइम करेंगे सेक्शन 2 में तो उनका केस कम्पाउंड हो जायगा। लीगल प्रैक्टिशनर अगर क्राइम करता है तो उसका केस कम्पाउंड हो जायगा। और इसलिए मैंने कहा कि 50 रुपये का जो है वह 50 रुपये तो पहले ही फाइन है, पहले गुनाह होता है तो 50 रुपये फाइन ले सकते हैं। लेकिन केस कोर्ट में रजिस्टर करने के बाद, अगर वापस लेते हैं तो ज्यादा पैसा लेना चाहिए। नाट एक्सीडिंग फिफ्टी रुपीज जो लिखा है उसकी जगह नाट एक्सीडिंग हन्ड्रेड रुपीज हो जाय यह मेरा संशोधन है। उसमें हन्ड्रेड रुपीज लेना ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है। सबजेक्ट टु सच कंडीशंस ऐज मे बी प्रेस्क्राइब्ड यह होने से ऐसी बात नहीं होगी कि हन्ड्रेड ही देना होगा। इसलिए 50 के बजाय उसके लिए 100 का प्राविजन होना चाहिए, यह मेरा संशोधन है।

15 hrs.

श्री श्रीचन्द गोयल : यह मिस्टर पाटिल ने जो संशोधन रखा है मैं उसका विरोध करता हूं। मिस्टर पाटिल ने यह नहीं समझा कि यह जो जुर्माना लग रहा है, यह केवल अधिकारियों पर नहीं लग रहा है बल्कि जो नागरिक हैं, वह भी यदि कोई अपराध करते हैं .....

श्री देवराव पाटिल : मैंने पहले ही बताया कि नागरिक कभी आपस में समझौता करने नहीं जायगा। उसके पास इतना पैसा ही नहीं है। तो वह इसके लिए नहीं जायगा।

श्री श्रीचन्द गोयल : आप अपनी बात कह चुके हैं। आपने यह समझा ही नहीं है कि यह 50 रुपये से 100 रुपये बढ़ाने की जो सिफारिश कर रहे हैं इसमें नागरिकों पर भी बोझा आयेगा क्योंकि किसी नागरिक के अपराध का केस आता है और उसके बाद यह धारणा अधिकारी की बनती है कि उसने अपराध किया या अपराध करने की कल्पना उसके बारे में बनी और उस पर जुर्माने के सिलसिले में कोई क्रिमिनल कार्यवाही चली तो 50 रुपये तक देने पर फैसला हो सकता है। आपस में फैसला होने पर 50 रुपया अधिक से अधिक रखा है, उसमें दस रुपया भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। कोई 50 रुपया लेना जरूरी नहीं है। आपके कहने के अनुसार 100 रुपया रख दिया जाय तो यह नागरिक के विरुद्ध बात जाती है, उसके अहित में यह जाती है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। और जब जुर्माने की राशि 50 रुपये है इस कारण उस केस के सिलसिले में समझौता करते हुए 50 रुपये से अधिक की राशि नहीं रखी जा सकती। मैं समझता हूं कि उन्होंने इसको समझा नहीं है, इसलिए यह संशोधन दिया है, मैं इसका विरोध करता हूं।

SHRI K. S. RAMASWAMY: The maximum penalty fixed for the offence is Rs. 50. This clause deals with compounding of offences. When there is compunding, it means there is only a presumption of guilt and it is not proved. So it cannot be more than Rs. 50 maximum.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

Page 10, line 26,—*for* "fifty rupees", *substitute*—"one hundred rupees". (14)

The motion was negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That clause 24 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 24 was added to the Bill

MR. DEPUTY-SPEAKER: There are no amendments to clauses 25 to 32.

SHRI BENI SHANKER SHARMA (Banka): Sir, I have an amendment to clause 30.

MR. DEPUTY-SPEAKER: That was not moved at the proper time. It is not on record. You are too late. I am sorry.

SHRI BENI SHANKER SHARMA: I shall just read out from the proceedings of the House dated 18th February, 1969, and quote what you have been pleased to say on that day:

> "All the amendments were received and fresh notices were given. They were not there before. It is not very clear whether they had all been circulated. Therfore, it is not possible to put them to vote now. So, I shall put the clauses and amendments to vote on the next occasion."

This is what you have said.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are under a misconception. They ought to have been revived again by giving notice. I am very sorry.

SHRI BENI SHANKAR SHARMA: You had said that all the amendments were revived and fresh notices were given.

MR. DEPUTY-SPEAKER The revival will take place after the notice. If you want to say something on the clause, I will permit you. There is no question of any amendment.

SHRI BENI SHANKER SHARMA: My amendment is to the effect that instead of the State Government, the rule-making power should be taken by the Central Government. I have suggested that the word "State" should be substituted by "Central" and the words "with the approval of the Central Government" should be deleted.

This is a Central enactment, and I do not understand why the State Governments should be allowed to make rules. For the purposes of uniformity, it is the Central Government that should have the power of making rules. That is my only submission.

SHRI S. M. BANERJEE: Sir, I rise to oppose this. More powers should be given to the States.

SHRI K. S. RAMASWAMY: We have given the power to the States to frame the rules. Different systems prevail in different States. For instance, with regard to the naming of the child, we do not know in how many days the name is given in the different States. So, it is better to leave all these things to the States.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am putting to the vote clauses 25 to 32. The question is:

> "That clauses 25 to 32 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 25 to 32 were added to the Bill.

Clause 1—(Short title, extent and Commencement)

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is a Government amendment. It is No. 7.

Amendment made:

Page 1, line 6, *for* " 1968" *substitute* "1969" *(Shri K. S. Ramaswamy)*

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is one amendment to the Enacting Formula by the Government. It is amendment No. 6.

Amendment made:

Page 1, line 1, *for* "Nineteenth" *substitute* "*Twentieth*" (*Shri K. S. Ramaswamy*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended was added to the Bill.

The Title was added to the Bill

SHRI K.S. RAMASWAMY: I move:

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER Motion moved:

"That the Bill, as amended, be passed."

SHRI TENNETI VISWANATHAM: Sir, As I said, there are about 52 lakhs of persons who will be born every year, and hereafter, on the passing of this Bill, the parents children will have to be born each with Rs. 50 in its hands, the fingers, in order to pay the fine, because their parents or relations or their keepers or somebody else might fail to report about their birth. This is the great gift which the Home Ministry is giving to the masses of this country.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am putting the motion to the vote. The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

12.10½ hrs.

UNION TERRITORIES (SEPARATION OF JUDICIAL AND EXECUTIVE FUNCTIONS) BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): Sir, I beg to move:

"That the Bill to provide for the separation of judicial and executive functions in Union Territories, as reported by the Joint Committee, be taken into consideration."

15.11 hrs.

[SHRI VASUDEVAN NAIR *in the Chair*]

This Bill was referred to a Joint Committee of both the Houses. The Joint Committee went thoroughly in the entire scheme of the Bill. After holding several sittings, this Bill was amended in certain respects and the Bill as amended by the Joint Committee is now before the House. Many amendments which have been moved, particularly by Shri Srinibas Misra, were also considered by the Joint Committee, but none of them has been incorporated. I will briefly explain why it is so. There is no minute of dissent and so it can be safely presumed that those hon. members who served on the Committee not only agree with the scheme which is unexceptionable but also with the details set out in the clauses.

Mainly this Bill seeks to achieve the object set out in article 50 of the Constitution. It is one of the Directive Principles that the "State shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State." While drafting the Bill, we have taken most of the provisions from the Punjab (Separation of Judicial and Executive Functions) Act and the Bombay (Separation of Judicial and Executive Functions) Act of 1951. This provides for the classification of the magistracy into judicial magistrates and executive magistrates and investing judicial magistrates with the function of trial and disposal of cases and the executive magistrates with the power of enquiring into and disposing of matters of a non-judicial character. The principal regarding classification has been set out in clause 5. Clause 3 seeks to amend the Cr. P.C. in the manner and to the extent specified in the Schedule to the Bill.